भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1445 का उत्तर

मध्य प्रदेश तथा मुंबई, कोंकण और संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र में लंबित रेल लाइन

1445. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं;

(ख) कितनी रेल लाइनों के आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और सिगनल प्रणाली का कार्य प्रारंभ हो गया है;

(ग) विशेषकर संभाजी नगर (औरंगाबाद) जिले का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश तथा मुंबई, कोंकण और संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र में कितनी रेल लाइनों का कार्य लंबित है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लंबित परियोजनाओं के परियोजना-वार कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

S.K

मध्य प्रदेश तथा मुंबई, कोंकण और संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र में लंबित रेल लाइन के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री ज्ञानेश्वर पाटील, श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे के अतारांकित प्रश्न सं. 1445 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

<u>महाराष्ट्र</u>

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोनों में आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं और संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिला सहित महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए लागत की 5,877 कि.मी. कुल लंबाई वाली 41 परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन 23 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1,926 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

S.K

इस कार्य की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
नई लाइन	16	2017	166	8,529
आमान परिवर्तन	2	609	312	3,332
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	23	3251	1448	19,376
कुल	41	5877	1926	31,236

इसके अलावा, महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण उच्च गति बुलेट गाड़ी परियोजना पर निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। अब 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। पुलों, जल सेतुओं आदि का कार्य आरंभ कर दिया गया है। समुद्र के नीचे लगभग 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए 3 टीबीएम के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। इसी बीच, टीबीएम के कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक कार्य जैसे शॉफ्ट का निर्माण आदि भी शुरू कर दिए गए हैं।

पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा भी महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारों के लगभग 178 मार्ग कि.मी. महाराष्ट्र में स्थित है, जो पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 12% है। महाराष्ट्र में न्यू घोलवड से न्यू वैतरणा तक इस परियोजना का 76 कि.मी. हिस्सा पहले ही कमीशन कर दिया गया है। पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा की जेएनपीटी से संपर्कता होने से बंदरगाह से दिल्ली एनसीआर तक कार्गो और कंटेनर यातायात को संभालने की क्षमता में वृद्धि करेगी।

S.K

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं हाल ही में स्वीकृत की गई हैं:-

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	लागत (करोड़ रुपये में)
1.	मनमाड़-इंदौर नई लाइन (309 कि.मी.)	16,321
2.	जालना-जलगांव नई लाइन (174 कि.मी.)	5,804
3.	औरंगाबाद- अंकाई दोहरीकरण (98 कि.मी.)	961
4.	परभणी - परली - बैजनाथ दोहरीकरण (65 कि.मी.)	770
5.	जलगांव - मनमाड़ चौथी लाइन (160 कि.मी.)	2,574
6.	भुसावल - खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 कि.मी.)	3,285

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है :-

अवधि	परिव्यय
2009-14	1171 करोड़ रुपए/वर्ष
2024-25	15,940 करोड़ रुपए (13 गुना से अधिक)

S.K

2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार हैः-

अवधि	कमीशन किए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	292 कि.मी.	58.4 कि.मी./वर्ष
2014-24	1830 कि.मी.	183 कि.मी./वर्ष (3 गुना से अधिक)

मुंबई और निकटवर्ती क्षेत्रों में संकुलन कम करने और यात्रियों की भावी मांगों को पूरा करने के लिए, 8,087 करोड़ रुपए की लागत पर मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-II, 10,947 करोड़ रुपए की लागत पर एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपए की लागत पर एमयूटीपी-IIIए को स्वीकृत किया गया है। मुंबई और निकटवर्ती क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ करोड़ में)
1	सीएसएमटी-कुर्ला पांचवीं एवं छठी लाइन (एमयूटीपी-II) (17.5 कि.मी.)	891
2	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली छठी लाइन (एमयूटीपी-II) (30 किलोमीटर)	919
3	गोरेगांव-बोरीवली से हार्बर लाइन का विस्तार (एमयूटीपी-IIIए) (7 किलोमीटर)	826
4	बोरीवली-विरार पांचवीं एवं छठी लाइन (एमयूटीपी-IIIए) (26 कि.मी.)	2184

S.K

5	विरार-दहाणु रोड की तीसरी एवं चौथी लाइन (एमयूटीपी-III) (64 कि.मी.)	3587
6	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (एमयूटीपी-III) (30 किलोमीटर)	2782
7	एरोली-कलवा (एलीवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (एमयूटीपी-III) (4 कि.मी.)	476
8	कल्याण-आसनगांव चौथी लाइन (एमयूटीपी-IIIए) (32 कि.मी.)	1759
9	कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी लाइन (एमयूटीपी-IIIए) (14 कि.मी.)	1510
10	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (67 कि.मी.)	792
11	नायगांव-जूचन्द्रा दोहरी कॉर्ड लाइन (6 कि.मी.)	176
12	निलाजे-कोपर दोहरी कॉर्ड लाइन (5 कि.मी.)	338

<u>मध्यप्रदेश</u>

मध्यप्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोनों में आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

S.K

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं सहित मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 81,797 करोड़ रुपए लागत की 5,345 कि.मी. कुल लंबाई वाली 28 परियोजनाएं (08 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन 18 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1,952 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 36,898 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

कार्य की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
नई लाइन	08	1962	468	11,091
आमान परिवर्तन	02	809	380	5,220
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	18	2574	1104	20,587
कुल	28	5345	1952	36,898

S.K

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं हाल में स्वीकृत की गई हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	मनमाड़-इंदौर नई लाइन (309 कि.मी.)	16,321
2.	भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 कि.मी.)	3,285

मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली निम्नलिखित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार हैं:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	632 करोड़/वर्ष
2024-25	14,738 करोड़ रुपए (23 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	145 कि.मी.	29 कि.मी./वर्ष
2014-24	2249 कि.मी.	224.9 कि.मी./वर्ष (लगभग 8 गुना)

S.K

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बड़ी लाइन नेटवर्क को 100 प्रतिशत विद्युतीकृत कर दिया गया है।

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा तीव्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के भाग को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना/परियोजनाओं स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशेष स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

****

S.K